कृषि अर्थव्यवस्था को अनलॉक करने के लिए महिला किसानों को कैसे सशक्त बनाया जाए

हेमंत सिक्का
अध्यक्ष, महिंद्रा फार्म इक्विपमेंट

परिदृश्य:

तेलंगाना के जहीराबाद में मिस्बाह, पेशे से किसान और ट्रैक्टर चलाने वाले प्रशिक्षक, की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। शादी के बाद, उसने अपने पति को जहीराबाद जाने के लिए मना लिया, जहाँ वह ट्रैक्टर–ड्राइविंग कार्यक्रम में सम्मिलित हो गई। कार्यक्रम में 80 पुरुषों के बीच वह अकेली महिला थीं। अपने अनुभव पर विचार करते हुए, मिस्बाह ने कहा, *'मेरे सहपाठी उत्सुक थे और प्रशिक्षण के बाद मेरी योजनाओं के बारे में मुझे चिढ़ाते थे। लेकिन अपने पति के समर्थन से मैं लगी रही और समय के साथ एक छात्रा से प्रशिक्षक की ओर बढ़ती गई।'*

उनकी यात्रा ने 40 अन्य महिलाओं को कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया। मिस्बाह को यह जानकर पूर्णता मिली कि उसके साहस ने न केवल उसे पुरुषों से जुड़े कौशल को सीखने की अनुमति दी, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। उन्हें अनुभव हुआ कि ग्रामीण समुदायों में उनके जैसी महिलाओं का अत्यधिक प्रभाव हो सकता है। 'इस अनुभव ने मेरे विश्वास को बढ़ावा दिया कि महिलाएं जो कुछ भी ठान लेती हैं उसे प्राप्त कर सकती हैं।'

भारत के ग्रामीण इलाकों में, जब अपने परिवार की कृषि भूमि से पर्याप्त आय प्राप्त करने की बात आती है तो कई महिलाओं को प्रायः अनदेखा कर दिया जाता है। ऐसा खेती में सक्रिय रूप से सम्मिलित होने के बाद भी है। वे भारत की कृषि अर्थव्यवस्था

के अज्ञात नायक हैं, जो अपने परिवार की कृषि भूमि के बोझ का एक बड़ा भाग वहन करते हैं, क्योंकि उनके पति या पत्नी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार की खोज में शहरी केंद्रों में जाने के लिए विवश होते हैं।

देश के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक के रूप में, कृषि ने पिछले दशक में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जो देश की जीडीपी में लगभग 20 प्रतिशत का योगदान देता है। यह देश के 45 प्रतिशत से अधिक कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है, जिसमें महिलाएँ उस कार्यबल का लगभग आधा भाग हैं। यह कहना पड़ेगा कि लगभग कि भारत की लगभग 80 प्रतिशत महिलाएँ नियोजित कृषि में लगी हुई हैं।

घरेलू आय बढ़ाने के अलावा, इन महिलाओं को प्राथमिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने का भी काम सौंपा जाता है, जैसे कि अपने परिवार के भोजन का प्रबंधन, घरेलू काम–काज और अपने बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना।

उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बाद भी, लैंगिक रूढ़िवादिता, सामाजिक प्रतिबंध और पारंपरिक भूमिका अपेक्षाओं की व्यापकता, खेती में ज्ञान और प्रौद्योगिकी तक महिलाओं की पहुँच में बाधा उत्पन्न करती है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता कम होती है। पीएलएफएस 2021–2022 के अनुसार, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर 68.9 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण पुरुषों की साक्षरता दर 83.5 प्रतिशत और शहरी महिलाओं की 84 प्रतिशत है। मई 2020 की भारत में कृषि मजदूरी (एडब्ल्यूआई) रिपोर्ट के अनुसार, यह भी चिंताजनक है कि खेती में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बाद भी, पुरुषों और

https://doi.org/10.52151/aet2024481.1707

महिलाओं के बीच मजदूरी बराबर नहीं है।

इन चुनौतियों के बाद भी, महिला किसान अपार प्रेरणा का स्रोत हैं क्योंकि वे अपनी भावना में एक चिंगारी के साथ देश की सेवा करती हैं।

इसे देखते हुए, देश को भोजन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए, खेती में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए नीति निर्माता क्या कदम उठा सकते हैं? विशेष रूप से कृषि के साथ–साथ उभरती कृषि प्रौद्योगिकियों के लिए सरकारी समर्थन के संदर्भ में। कृषि के स्त्रीकरण की पहले से ही स्थापित गति को आगे बढ़ाने के लिए सुधारों का अगला सेट क्या हो सकता है?

महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) में विकसित करना

महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 'सबका साथ सबका विकास' के माध्यम से महिलाओं को उनके ज्ञान और कौशल का पोषण करके सशक्त बनाने सहित विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। एसएचजी शिक्षा, पोषण और जन्म नियंत्रण उपायों को अपनाकर अपने परिवार सहित उनकी शारीरिक और भावनात्मक लचीलापन को सुदृढ़ करने में सहायता कर सकते हैं। सरकार की सबका साथ पहल सराहनीय है। 9 करोड़ महिलाओं वाले 84 लाख एसएचजी को हमारे देश के सामाजिक–आर्थिक ढाँचे में बदलाव के लिए एकीकृत किया गया है। वहाँ से, इन महिला–नेतृत्व वाले एसएचजी को महिला–नेतृत्व वाले एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) में बदलने से 'लखपति दीदी' बनाने में काफी सहायता मिल सकती है। वे सामूहिक रूप से प्रतिभागियों को फसल की पसंद, माइक्रोफाइनेंस तक पहुँच और प्रभावी उत्पाद विपणन पर मार्गदर्शन कर सकते हैं, धीरे–धीरे बेहतर कमाई के लिए पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने वाले सूक्ष्म उद्यमों में बदल सकते हैं, और ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कृषि पर सरकार का जोर, कृषि क्षेत्र में भंडारण, आपूर्ति श्रृंखला और ब्रांडिंग के आधुनिकीकरण की प्रतिबद्ध ता इस दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिससे खेती के माध्यम से मूल्यवर्धन और आय में वृद्धि होती है, और किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होता है।

महत्वपूर्ण कृषि उपकरणों तक पहुँच प्रदान करने वाले कार्यक्रम

बहुत अधिक महिलाएं अपने उपकरण चलाने में रुचि रखती हैं। एसएमएएम जैसी सरकारी पहल सही दिशा में एक कदम का संकेत देती है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत किसानों को कृषि मशीनरी खरीदने पर 50 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है, जिसमें महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। सभी राज्यों में कार्यान्वयन के साथ, सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह इन कृषि उपकरणों को प्राप्त करने के लिए वहन करने योग्य वित्त तक अधिक पहुँच सुनिश्चित करे, साथ ही उनका नमूना लेने के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र भी स्थापित करे। ऐसा कहने के बाद, भारत को फसल के जीवनचक्र के दौरान विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए वहन करने योग्य समाधान के लिए ट्रैक्टरों से परे कृषि मशीनीकरण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए: चावल रोपाई तकनीक की श्रेष्ठतर पहुँच से कड़ी मेहनत वाली मैन्युअल रोपाई की तुलना में कठिन परिश्रम को कम किया जा सकता है, जो प्रायः उड़ीसा, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे धान राज्यों में देखा जाता है। राज्य सरकारें भी यहाँ सशक्त भूमिका निभा सकती हैं।

महिलाओं के लिए, महिलाओं द्वारा समाधान विकसित करना और संचालित करना

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) अपने अनुसंधान के माध्यम से खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है। वे खेतों में प्रौद्योगिकी को अपनाने, ग्रामीण नवाचार को आगे बढ़ाने, खेती के विधियों में सुधार करने, जलवायु–लचीली और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं, साथ ही कृषि–तकनीकी स्टार्टअप का भी समर्थन करते हैं। पूरे भारत में आईसीएआर के 113 संस्थानों और 74 कृषि विश्वविद्यालयों का नेटवर्क, उन्हें विश्व स्तर पर सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक बनाता है।

हालाँकि, यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है कि ये केंद्र अधिक महिलाओं को नामांकित करने की दिशा में काम करें और खेती में महिलाओं से संबंधित आवश्यक शिक्षा और संवेदनशीलता प्रदान करने के लिए एक अनुरूप दृष्टिकोण के साथ महिला–अनुकूल कृषि समाधानों के विकास को तेजी से ट्रैक करें। एआई, एमएल, आईओटी और ऐप–आधारित समाधान जैसी नए युग की प्रौद्योगिकियों का एकीकरण भी खेती में महिलाओं के लिए एक परिवर्तनकारी बदलाव को चिह्नित करने में सहायता कर सकता है।

निजी क्षेत्र भी महिला किसानों के लिए विकसित कम खर्च वाला और कृषि सुलभ समाधान प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। ग्रामीण महिलाओं को समावेशी अनुभव करने, और कृषि में आगे योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के नवाचार की आवश्यकता है।

निष्कर्षतः, भारत को नीति और अनुसंधान में एक एकीकृत घटक के रूप में महिला परिपेक्ष्य को सम्मिलित करने के साथ कृषि और विशेषकर ग्रामीण भारत में लैंगिक विषयों के आसपास मुख्य दक्षताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। खेती में महिलाओं की प्रगति और विकास को भारत, जो कि विश्व की रोटी का स्रोत बन गया है, की प्रतिष्ठा बढ़ाने के अलावा, देश के समग्र विकास लक्ष्यों से निकटता से जोड़ा जाना चाहिए।

जैसा कि फॉर्च्यूनइंडिया.कॉम में प्रकाशित हुआ है।